



बिहार विधान परिषद

205वां शीतकालीन सत्र

9 नवंबर 2023

: [जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 26

पूर्ण थाना का दर्जा कबतक

*50 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले में कई थानों का निर्माण हो चुका है और वे सुचारु रूप से कार्य भी कर रहे हैं, परंतु इन्हें पूर्ण थाना का दर्जा नहीं मिला है;

(ख) क्या यह सही है कि गया जिले का मोहनपुर थाने का निर्माण हो चुका है और यह कार्य भी रहा है, परंतु इसे पूर्ण थाना का दर्जा नहीं मिल पाया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया जिले के ऐसे सभी थानों को पूर्ण थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

जर्जर भवनों की मररम्मती

*51 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि तिरहुत रेंज, मुजफ्फरपुर में थाना के भवन जर्जर हैं और उनकी छतों से प्लास्टर टूट-टूटकर गिर रहे हैं जिससे थाना में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की जान को खतरा है, साथ ही साथ राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति की सूचना मिलती रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के पुलिसकर्मी अपनी होली-दीवाली, छठ और ईद पर्वों में भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहते हैं, उन्हें बेतहर सुविधा की दरकार है न कि जर्जर थाना भवनों में जान ,खतरे में डालकर उन्हें रखा जाना चाहिए;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत तिरहुत रेंज सहित राज्य के सभी थानों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

विभागीय कार्रवाई करने पर विचार

*52 श्री संजय पासवान (विधान सभा):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की प्रतिष्ठित संस्था 'इमारत-ए-शरिया' के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक:- 11.10.2023 को राज्य के पुलिस महानिदेशक से मिलकर नवादा जिला अन्तर्गत परनाडाबर थाना परिसर में समीना खातून नामक महिला के साथ थानाध्यक्ष द्वारा किये गये गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार, उनके पुत्र कैफ अंसारी के साथ मारपीट और दोनों मां-बेटे को हाजत में बंद करके उनके आर्थिक दोहन की शिकायत से संबंधित आवेदन दिया था जिसका ई.नं.- 2172302/डी.जी.पी. है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस मामले की पुलिस मुख्यालय के स्तर से उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध विधिसम्मत और विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आदेश निर्गत करने का विचार कबतक

*53 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या मंत्री, वित्त विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प सं.- 1470, दिनांक- 27.09.2016 द्वारा सात निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के 12वीं पास छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा

प्राप्त करने हेतु स्टूडेंट क्रेडिट कोर्ड योजना अंतर्गत 4 लाख की सहयोग राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या यह सही है कि आमना सुभानी, पिता- मो. मसूद रजा को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत Ref. No. - 1478/D.R.C.C., Dated- 11.09.2017 को 4 लाख रुपये की राशि फीस के आधार पर निर्देशित सिंडिकेट बैंक (केनरा बैंक) किदवईपुरी पटना द्वारा दी गई;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त लोन पढ़ाई खत्म होने के तीन साल बाद 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाना था लेकिन चिन्हित बैंक द्वारा 9.95 प्रतिशत की दर से लोन निर्गततिथि से ब्याज मांगा जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है;

(घ) क्या यह सही है कि बैंक द्वारा यह तुगलकी फरमान बिहार के सभी छात्र-छात्राओं पर लागू किया जा रहा है, जो लोन लिए हुए हैं उन छात्रों का खाता बैंकों द्वारा बंद किया जा रहा है, छात्र-छात्राओं के आगे की लोन की किस्त रोकੀ जा रही है, बैंक द्वारा छात्रों और अभिभावकों को Legal Notice भी दी जा रही है, अभिभावक का भी बैंक खाता निष्क्रिय किया जा रहा है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के छात्र-छात्राओं के हित में संबंधित बैंकों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्रों की दी जाने वाली लोन के ब्याज की वसूली नियमानुसार करने हेतु आदेश निर्गत करने के साथ लोन की अगली किस्त छात्रों को अविलंब उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

विस्तृत ब्योरा कबतक

***54 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रमिक एवं विभिन्न श्रम समूहों को निबंधित करने हेतु ई-श्रम पोर्टल श्रम विभाग द्वारा बनाया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ई-श्रम पोर्टल पर निबंधित विभिन्न सामाजिक समूहों के निबंधन के विस्तृत ब्योरा से सदन को अवगत कराना चाहती है ?

तटबंध का निर्माण कार्य पूर्ण कबतक

***55 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड क्षेत्र के बेलवा डैम से लेकर पूर्वी चम्पारण के जिले के पताही प्रखंड के देवापुर तक वागमती नदी पर 50 (पचास) करोड़ की लागत से 3 (तीन) कि.मी. लम्बा तटबंध का निर्माण कार्य वर्षों से किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि शिवहर जिला की सीमा तक करीब डेढ़ कि.मी. में तटबंध का आधा अधूरा काम हुआ है जबकि इससे आगे पूर्वी चम्पारण जिला के देवापुर तक करीब दो कि.मी. में काम शुरू नहीं हो पाया है;

(ग) क्या यह सही है कि तटबंध का निर्माण होने से करीब चार लाख की आबादी बाढ़ से तबाह होती रहती है, उसे फायदा होगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त तटबंध का निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

योजना कबतक

***56 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि यदि कोई गाड़ी चोरी हो जाती है और थाना उसे अपराधियों द्वारा शराब सप्लाई के क्रम में जब्त कर लेता है तो गाड़ी मालिक को अपनी गाड़ी कोर्ट से रिलीज करवाने पर जब्त गाड़ी का बीमा क्लेम का 25 प्रतिशत कोर्ट को चालान के रूप में जमा करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि इससे गाड़ी मालिक पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा इस नियम में बदलाव कर यह चालान शराब सप्लाई करने वाले अपराधियों से वसूलने की कोई योजना है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

व्यवस्था कबतक

***57 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड लौरिया की ग्राम पंचायत धोबनी धर्मपुर में कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई का साधन नहीं होने से किसानों को अपनी फसल उगाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल चक्र प्रभावित होता है;

(ख) क्या यह सही है कि फसल चक्र प्रभावित होने से किसानों को भुखमरी का शिकार होना पड़ता है, जिससे किसान आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान जीवन जीने को विवश है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में सिंचाई के लिए नलकूप एवं बोरिंग की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

चयन करने का विचार कबतक

*58 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायतों के लिए 07 सवारी वाहन खरीदने हेतु, जिसमें चार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को अनुदान दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के अधीन दसवें चरण में काफी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, किंतु सात की संख्या रहने के कारण कई आवेदनकर्ता को इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रत्येक पंचायतों के लिए 07 आवेदकों के स्थान पर 20 आवेदकों का चयन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

क्रियान्वयन कबतक

*59 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी कोशी तटबंध के पूर्वी भाग में सुपौल एवं सहरसा जिले की सैकड़ों एकड़ भूमि सीजेज वाटर के कारण जलप्लावित रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्वी कोशी तटबंध के पूर्वी बाहरी भाग में बारह महीने जलजमाव के कारण खेती नहीं हो पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जलजमाव वाली सैकड़ों एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए किसी योजना के क्रियान्वयन का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रखंड तक गंगा जल उपलब्ध कबतक

*60 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि तेतर डैम, गया तक गंगा जल परियोजना पहुंचाई गई है, जो नवादा जिला के मेसकौर प्रखंड से 25 किलोमीटर दूर है;

(ख) क्या यह सही है कि मेसको प्रखंड में जल स्तर काफी गहराई में चले जाने के कारण ग्रामीणों को पानी का संकट का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तेतर डैम गया से गंगा जल परियोजना के तहत पाईप लाईन के माध्यम से मेसकौर प्रखंड तक गंगा जल पहुँचाया जा सकता है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

कठिनाई को दूर करने का उपाय कबतक

*61 श्री सम्राट चौधरी (विधान सभा):

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि परिवहन प्राधिकार द्वारा पूर्व में शादी, शव यात्रा, बारात, राजनीतिक पार्टियों की रैली एवं तीर्थ यात्रा हेतु, 7, 14 और 28 दिन का अस्थायी परमिट दिया जाता था, जिसे बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि व्यवसायिक वाहनों में VLTID का शुल्क अन्य प्रांतों में 3000/- और बिहार में वाहन मालिकों से बिना प्राप्ति रसीद के 10 से 20 हजार लिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा वाहन मालिकों पर जुर्माना किया जाता है, उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं करने का शपथ-पत्र लिया जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि इंश्योरेस फेल वाहन का दण्ड शुल्क 2000/- होने के बावजूद वाहन संख्या- BR44P-1537 के मालिक से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक- 30.09.2023 की बैठक में 3 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, साथ ही वाहन मालिक से आवेदन लिखने में त्रुटि होने पर प्रमंडलीय आयुक्त मुजफ्फरपुर द्वारा 10 से 20 हजार जुर्माना वसूला जाता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यवसायिक वाहनों के परिचालन में हो रही कठिनाई को दूर करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

आकलन करने का विचार कबतक

*62 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या मंत्री, **योजना एवं विकास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि हाल के वर्षों में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में संतोषजनक प्रगति हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के सभी राज्यों में कम है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास समयबद्ध कार्य योजना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के औसत प्रति व्यक्ति आय के समकक्ष कब आ सकेगा, क्या सरकार इसका आकलन करने का विचार रखती है ?

प्रतिमा का निर्माण कबतक

*63 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश जिलों में अति पिछड़ा विभाग द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उन छात्रावासों में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में प्रतिमा का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का विचार

*64 श्री मंगल पांडेय (विधान सभा):

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सिसवन प्रखंड की पंचायत भागड़ में वार्ड 9 की नई बस्ती में 800 की आबादी है, लेकिन इस बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि वार्ड 9 के लाभार्थियों को केंद्र संख्या 21, संख्या 130, संख्या 24 में जोड़ दिया गया है, जिसके कारण लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार प्रत्येक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलना अनिवार्य है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वार्ड संख्या 9 में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबत, नहीं तो क्यों ?

कितने लोगों पर कार्रवाई

*65 श्री जनक राम (मनोनीत):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि समस्त बिहार में आए दिन दलित रविदास समाज के लोगों को टारगेट कर हत्याएं की जा रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अगर दलित समाज के लोगों की हत्याएं होती हैं तो उनके आश्रितों को एक सरकारी नौकरी एवं मुआवजा राशि दी जाएगी;

(ग) क्या यह सही है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा अबतक सरकार ने कितनी कार्रवाई की है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह स्पष्ट करे कि राज्य में कितने दलित रविदास समाज के लोगों की हत्याएं हुईं तथा उसमें कितना केस दर्ज हुए तथा कितने लोगों पर कार्रवाई हुई ?

प्रतिमाह पेंशन भुगतान का विचार कबतक

*66 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह 400 से 500 रुपये मिलने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि वृद्धजनों को प्रतिमाह रुपया नहीं मिल पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि वृद्धजनों को जो वृद्धजन पेंशन मिल रहा है वह अभी के महंगाई के समय में काफी कम है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये करने एवं प्रतिमाह पेंशन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सिंचाई की व्यवस्था कबतक

*67 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत सासाराम प्रखंड के ग्राम कंचनपुर में काव नदी पर बांध निर्मित होने के बाद भी किसानों को अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि काव नदी पर बिहार सरकार द्वारा बांध करोड़ों रुपया की लागत से बनाया गया है, लेकिन नहर अर्धनिर्मित के कारण वहां के दर्जनों गांवों को पानी नहीं मिल पा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि इस समस्या से सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं जिला अधिकारी को सूचित किया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नहर का निर्माण कर काव नदी के दक्षिणी छोर पर बने बांध से दर्जनों गांवों को पानी एवं सिंचाई की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

घेराबंदी कराने का विचार कबतक

*68 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला अंतर्गत बथानी प्रखंड की पंचायत नैयली के ग्राम संरौजी एवं बंडी में कब्रिस्तान की बाउंड्री टूट-टूटकर खत्म हो चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं रहने से कब्रिस्तान की जमीन जानवरों का चारागाह बन गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आरक्षण का न्यूनतम लाभ

*69 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रिपोर्ट जारी कर दी गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कुल 190 ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या 1% से कम है, उन जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के पास क्या योजना है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि बिहार में आरक्षित श्रेणी यानी (ओबीसी, ईबीसी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) वर्ग में ऐसी कितनी और कौन-कौन सी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का न्यूनतम लाभ मिला है ?

नहर का जीर्णोद्धार कबतक

***70 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा प्रखंड के लाइन छोटी नहर चकरदहवा से सैदपुर होते हुए माधोपुर बड़ा अहरा तक करीब 2 कि.मी. नहर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर की वर्षों से खुदायी नहीं होने के कारण पूरी नहर में गाद भर जाने के कारण किसानों को खेत पटवन में काफी परेशानी हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों के हित में देखते हुए उक्त नहर का जीर्णोद्धार कबतक कराना चाहती है ?

आनंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कबतक

***71 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के मनसूरचक प्रखंड की गोविंदपुर पंचायत-2 में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का प्रस्ताव मंजूर है;

(ख) क्या यह सही है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का भवन अभी भी अधूरा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनसूरचक प्रखंड की गोविंदपुर पंचायत-2 में स्थित अर्द्धनिर्मित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कबतक

***72 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला अंतर्गत प्रखंड पानापुर की पंचायत कोन्ध से होते हुए प्रखंड तरैया की पंचायत डुमरी तक मही नदी से सिलटेसन प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी की ससमय सफाई नहीं होने से अतिक्रमणकारियों द्वारा नदी के किनारे मिट्टी भराई कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित नदी की साफ-सफाई कराने के साथ-साथ नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई कबतक

***73 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारुण से औरंगाबाद एन.एच. 02 पर बी.आर.बी.सी.एल., एन.पी.जी.सी.एल. श्री सीमेंट फ़ैक्ट्री तथा रेलवे रैक प्वाइंट, बारुण से लदान क्षमता से अधिक वाहन ओवरलोडिंग में चल रहा है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने ज्ञापांक 400, दिनांक- 31.03.2023 के द्वारा सीमेंट/क्लिकर/जिप्सम फ़लाईश की लोडिंग लदान क्षमता से अधिक नहीं करने देने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्राचार किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त ज्ञापांक के आलोक में संबंधित कर्मी द्वारा ओवरलोडिंग रोकने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

बसों को चलाने का विचार कबतक

***74 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के बथुआ बाजार से मीरगंज होते हुए पटना तक आने-जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि आवागमन का कोई साधन नहीं रहने के कारण आम लोगों के साथ ही साथ छात्र-छात्राओं को विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने में तथा आम लोगों को बथुआ बाजार से मीरगंज और पटना आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रास्ते पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को प्रतिदिन चलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

थाना भवन का निर्माण कब तक

***75 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दरभंगा जिला में लगभग सभी थानों के नए भवन का निर्माण हो चुका है, परंतु दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना का अभी तक भवन नहीं बना है, साथ ही साथ थाना का वर्तमान आवासीय भवन भी किसी काम का नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना का भवन निर्माण करवाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?
